



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 105 राँची, मंगलवार,

5 फरवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 फरवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-385/2014 का.-430 (HRMS)-- श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू के विरुद्ध नरेगा अन्तर्गत बुण्डू प्रखण्ड में टूंगड़ी को हराभरा करने हेतु सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण की योजना में अनियमितता बरतने, बगैर योजना स्थल का निरीक्षण किये कुल 23 योजनाओं के विरुद्ध कुल 47.515 लाख रुपये का भुगतान नियम विरुद्ध करने, फर्जी मस्टर रॉल के आधार पर बिना मस्टर रॉल सत्यापन के सरकारी राशि का भुगतान करने, नरेगा अन्तर्गत जॉब कार्ड, जॉब कार्डधारी मजदूरों के पास न होकर कार्यकारी एजेंसी एन०जी०ओ० द्वारा अपने पास रखने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने, योजनाओं के वगैर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के अग्रिम भुगतान का कार्य करने एवं ग्राम सभा का आयोजन भी फर्जी तरीके से करने संबंधी आरोप ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6387, दिनांक 01 सितम्बर, 2009 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-451/गो०, दिनांक 05 अगस्त, 2009 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8154, दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री कुमार ने पत्रांक- 06, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3481 दिनांक 24 जून, 2011 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-17(i)/गो०, दिनांक 17 जनवरी, 2012 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3571, दिनांक 12अ प्रैल, 2012 एवं संकल्प सं०-6504, दिनांक 19 मई, 2012 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

5. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-344, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

6. मामले के समीक्षोपरांत, उपायुक्त, राँची से श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों में सन्निहित सरकारी राशि की क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन की माँग की गई, जिसके आलोक में उपायुक्त, राँची के पत्रांक-181(i) दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा 78.69 लाख रु० सरकारी राशि क्षति के प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध विभाग स्तर पर पूरक प्रपत्र-‘क’ गठित कर विभागीय संकल्प सं०-3753 दिनांक 09 मई, 2016 द्वारा पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

7. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-119, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में सरकारी राशि की क्षति संबंधी पूरक प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप को प्रमाणित तथा प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप संख्या-2, 4 एवं 7 प्रमाणित, आरोप संख्या-3 एवं 6 आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-1 एवं 5 प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया गया है।

8. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(क) श्री कुमार द्वारा नरेगा अंतर्गत स्वीकृत कुल 23 वृक्षारोपण योजनाओं हेतु वगैर जिला से अनुमोदन प्राप्त किये अपने स्तर से दो स्वयंसेवी संस्था - उत्थान एवं ऊँ साईं खादी ग्रामोद्योग का चयन करते हुए इन्हें कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया एवं वगैर मापी, मस्टर रॉल के सत्यापन एवं योजना स्थल के निरीक्षण के विभिन्न तिथियों को कुल 47.515 लाख रु० के अग्रिम राशि दी गई। साथ ही इन योजनाओं में नरेगा के प्रावधानों के विपरीत मजदूरी का भुगतान खाता के माध्यम से सुनिश्चित नहीं किया गया।

(ख) स्वयंसेवी संस्थाओं को आवंटित कुल 23 वृक्षारोपण योजनाओं में की गई मापी के उपरान्त उत्थान संस्था के विरुद्ध 37,86,500/- (सैंतीस लाख छियासी हजार पांच सौ) रु० एवं ऊँ साई संस्था के विरुद्ध 6,07,500/- (छः लाख सात हजार पांच सौ) रु० की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर किया गया।

(ग) आरोपी के द्वारा स्वयं कभी भी योजना स्थल का निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं किया गया एवं कनीय अभियंता के प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् भी स्वयंसेवी संस्थाओं को अग्रिम का भुगतान किया गया।

(घ) आरोपी पदाधिकारी द्वारा बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये नरेगा अंतर्गत ग्रेड-1 पथ, चेक डैम, वृक्षारोपण एवं तालाब निर्माण की कुल 30 योजनाएं, जिनकी प्राक्कलित राशि 2,60,24,732/- रु० थी, प्रारंभ की गयी एवं इन योजनाओं के विरुद्ध कुल 34,75,000/- रु० अग्रिम का भी भुगतान विभिन्न अभिकर्ताओं को किया गया। इन सभी योजनाओं में प्रथम अग्रिम 15,000/- रु० एवं तदुपरान्त बिना किसी कार्य के एक-एक लाख रु० प्रति योजना अग्रिम राशि दी गई। बाद में उपायुक्त, राँची के आदेश से इन सभी योजनाओं को रद्द कर दिया गया।

9. अतः समीक्षोपरांत, श्री कुमार को निलंबित किया जाता है।

10. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भर्त्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	LALAN KUMAR (JHK/JAS/174)	श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुण्डू को निलंबित किया जाता है।	04/02/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
